लखनऊ, कानपुर और दिल्ली से प्रकाशित

प्रकाशन का 73वां वर्ष

स्वतंत्र भारत

लखनऊ
सोमवार, 19 अगस्त 2019 ई.
भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 4
सं. 2076 वि.

e-paper : swatantrabharat.net

वर्ष 73 | अंक 04 | नगर संस्करण | पृष्ठ 12 | मूल्य 3.00 रुपये

यत्र-तत्र

गड़बड़िया सुलझाओ वरना लोगों से कहूंगा धुलाई करो : गडकरी

2030 तक ऊर्जा की कमी से मुक्त हो सकता है भारत

ब्यूरो, लखनऊ।

इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यूपी स्टेट सेन्टर में रविवार को

-ऊर्जा स्वतंत्रता को लेकर आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ता ने व्यक्त किये विचार

भारत में 2030 तक ऊर्जा स्वतंत्रता के लिये अक्षय ऊर्जा का उपयोग विषयक एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज लखनऊ के महानिदेशक डा. भरत राज सिंह ने अपने विचार व्यक्त किये।

मुख्यवक्ता डा. भरत राज सिंह ने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सौर ऊर्जा, पवन और जैव द्रव्यमान और गैस माध्यम के रूप मे उपलब्ध हैं। इसके द्वारा वर्ष 2030 तक भारत को विद्युत ऊर्जा की कमी से मुक्त बनाया जा सकता है। वर्ष 2020 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने 175 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा का विद्युत दोहन कर राष्ट्रीय ग्रिड में भेजने की योजना बना रखी है। उस 175 गीगा-वाट में से भारत सरकार ने सौर उत्पादन से 100 गीगा-वाट, पवन ऊर्जा से 50 गीगा-वाट, मिनी-हाइड्रो, बायोमास और बायोगैस आदि से 25 गीगा-वाट की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि बजट 2019 के दौरान भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के माध्यम से 200 गीगा-वाट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से निर्धारित किया है। यह 2030 तक न केवल जलवायु गिरावट के संरक्षण के लिए जोड़ देगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को कई गुना बदलाव देगा और भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता में भी विकसित कर सकता है। इस विद्युत शक्ति का निर्यात भविष्य में पड़ोसी देशों को अंतरराष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से कर सकता है। कार्यक्रम के प्रारम्भ में संस्था के अध्यक्ष आरके त्रिवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के नेशनल कौंसिल सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष कीर्ती सिंह ने किया तथा समापन मानद सचिव प्रभात किरण चौरसिया के धन्यवाद ज्ञापित किया।